19

सरकारी बजट और कर निर्धारण

- आपके आसपास सरकार की क्या भूमिका नजर आती है? आपस में चर्चा करें
- क्या आपको मालूम है कि सार्वजनिक सुविधाएँ मुहैया करवाने और अन्य गतिविधियों के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाती है?
- अपने क्षेत्र में आने वाले अखबारों को पढ़कर पता लगाइए कि सरकार कहाँ–कहाँ खर्च करती है। उनकी एक सूची बनाइए।

19.1 सरकार की भूमिका

आधुनिक समाज में सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। इनमें बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करना और पुलिस के माध्यम से आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा सरकार का एक बड़ा दायित्व नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी है। सार्वजनिक सुविधा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो यह उस क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए उपयोगी होगी। किसान अपने पंपसेट चला सकते हैं, कारखानों, कार्यालयों, दुकानों और घरों में इस बिजली का उपयोग किया जा सकता है। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित न हो। इसके लिए इसकी कीमत अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति के अन्दर रखनी चाहिए ताकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से कर सकें।

चित्र 19.1 : सार्वजनिक सुविधाएँ

लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही है। आप लोगों ने काम करने का अधिकार और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के बारे में सुना होगा। इस कानून के तहत सरकार की यह ज़िम्मेदारी तय की गई है कि वह ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक का कार्य उसकी माँग पर उपलब्ध कराएगी। यह कार्य लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्ध कराना होगा और इसके लिए होने वाला पूँजीगत खर्च और मज़दूरी का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों जैसे चेकडैम, वॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाएँ, सड़कें, तालाबों आदि का निर्माण किया जा सकता है।

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी सरकार की अहम भूमिका है जहाँ उसे कई कार्य करने होते हैं। इसे हम 'खाद्य सुरक्षा' अध्याय में पढ़ेंगे।

खाद्य सुरक्षा के संबंध में सरकार की भूमिका को बताइए।

सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है?

भारत सरकार ने अतीत में भी हेवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों की खुदाई और उसका परिष्करण (रिफाइनिंग) जैसे भारी उद्योग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बिना औद्योगिकीकरण बहुत ही कठिन होता। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं और कृषि विस्तार कार्यों पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च भी कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।

सरकार की एक और भूमिका नियमन (Regulatory) को लेकर है। नियमन के तहत कई तरह के कानून बनाए जाते हैं जो व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए आप खाने की चीजों के पैकेट्स खरीदते समय उन पर **FSSAI** का निशान देखते होंगे। इसका पूरा नाम – 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया' है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों और कंपनियों द्वारा बेची जा रही खाने–पीने की सामग्री एक निश्चित सुरक्षा के मापदण्डों का पालन करें। कुल मिलाकर FSSAI खाद्य सामग्री को विभिन्न नियमों और निगरानी के ज़रिए सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के प्रति जवाबदेह है। इसके तहत खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे चिप्स, नूडल्स फलों के जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले परिरक्षक (Preservative) पदार्थ के मापदंड भी FSSAI के द्वारा ही तय होते हैं। यह समय–समय पर इसके नमूने (Sample) भी लेता रहता है ताकि वह इस बात की जाँच कर सके कि उसके द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन हो रहा है या नहीं। यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सील बंद खाद्य पदार्थों पर उत्पादन एवं समाप्ति की तिथि व मात्रा जैसी सूचनाएँ अवश्य हों।

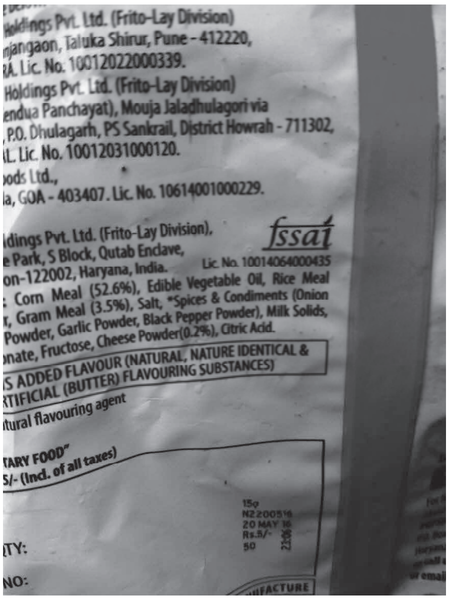

चित्र 19.2 : उत्पादित वस्तु पर **FSSAI** का निशान

ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ सरकार नियमन को लेकर अहम भूमिका निभाती है। मुद्रा और साख नामक अध्याय में आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के बारे में पढ़ा होगा। भारत में यह बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों के क्रिया–कलापों पर नियंत्रण रखती है।

ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाएँ जिनका सामूहिक रूप से उपयोग होता हो। क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति तक यह सुविधा समान रूप से पहुँचती हैं? चर्चा करें।

सरकार के ऐसे कौन–कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं?

19.2 सरकारी बजट

सरकार की अनेक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसे कई कार्य करने पड़ते हैं जिनमें से कुछ की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करने और फिर खर्च करने की ज़रूरत होती है। इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, उसे लोगों से कर (टैक्स) के रूप में एकत्र की जाती है। सरकार कई तरह के कर लगाती है जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। सरकार जो कर वसूल करती है, उसे राजस्व कहते हैं। सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है। सरकार के राजस्व और उसके खर्च का पूरा लेखा–जोखा बजट कहलाता है। बजट में इन बातों का विवरण होता है –

1. सरकार कितना पैसा खर्च करेगी।
2. अलग–अलग विभागों को खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, इसका विवरण अर्थात शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा आदि मदों पर कितना खर्च किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी होती है।
3. कौन–कौन से कर लगाए जाएँगे और इनसे कुल कितना राजस्व संग्रहित किया जाएगा? साथ ही किन–किन करों की दर में परिवर्तन किया जाएगा?
4. सरकार के खर्च अगर संग्रहित राजस्व से अधिक हैं तो कितनी राशि उसे उधार लेनी पड़ेगी।

हम यहाँ वर्ष 2016–17 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की कुछ मुख्य बातों की जानकारी दे रहे हैं। इससे यह अनुमान लग सकेगा कि बजट क्या होता है?

विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित प्रावधान –

– वर्ष 2016–17 में कुल 70,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो 2015–2016 की तुलना में 6 प्रतिशत ज़्यादा हैं।

– वर्ष 2016–17 में कुल राजस्व 62,000 करोड़ रुपए संग्रहित होगा जो 2015–2016 की तुलना में 5 प्रतिशत ज़्यादा है।

– वर्ष 2016–17 के लिए शिक्षा, सड़कों व पुलों, पेंशन, दवाइयों व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके विपरीत खाद्य एवं संग्रहण विभाग के लिए आवंटित राशि में काफी कटौती की गई है।

चित्र 19.3 : छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा

– वर्ष 2016–17 में बिक्री कर से 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

source – http:cgfinance.nic.in/budget doc/2016-17

सरकार अपने द्वारा किए जाने वाले कुल सार्वजनिक व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि क्यों करती है?

सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के बजट में कुछ क्षेत्रों में वृद्धि एवं कुछ क्षेत्रों में कमी क्यों की गई है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? चर्चा करें।

वर्ष 2016–17 में बिक्री कर से 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है। यदि यह राशि 6,000 करोड़ रुपए प्राप्त होती है तो सरकार इस परिस्थिति में क्या–क्या कर सकती है, चर्चा करें।

यद्यपि बजट सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे पारित करने में विधानमंडल की अहम भूमिका होती है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। राज्यों का बजट संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। साथ ही सभी करों और व्यय की जाने वाली राशि के लिए सरकार को संसद या विधानसभा से स्वीकृति लेनी होगी।

चर्चा कीजिए

1. बजट पारित करने के लिए विधानमंडलों की मंजूरी क्यों ज़रूरी है?
2. सरकार को खर्च करने और कर वसूलने की पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई है?

बजट पर संसदीय नियंत्रण के पीछे धारणा यह है कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बजट पर नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी राजस्व का सही उपयोग हो तथा कर संग्रहण करने की प्रणाली उचित और पारदर्शी हो। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट आम लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसके साथ ही लोक कल्याणकारी तथा देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। चूँकि बजट सरकार की योजनाओं और विचारों का दर्पण होता है इसलिए जनप्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार विकास के मार्ग में चलती रहे और इस दिशा से भटके नहीं।

संसद का बजट सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बजट पारित करने से पहले उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा की जाती है। विपक्ष सरकार के बजट पर बहस, आलोचना और रचनात्मक सुझाव देकर अहम भूमिका निभा सकती है। सरकार की जवाबदेही को लेकर आम लोगों की ओर से भी सीधा दबाव पड़ता है। यहाँ इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है –

19.3 जनता की भागीदारी और बजट

बजट सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को अमल में लाने का एक माध्यम होता है। पर्याप्त बजटीय प्रावधान और पैसे का समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम केवल वादे बनकर रह जाते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोजी रोटी अधिकार अभियान

"एक NGO के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) के तहत दाल या तेल को शामिल नहीं किया है, जबकि ये उसका चुनावी वादा था। कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दाल या तेल उपलब्ध करवाया जाता है। इतना ही नहीं, शनिवार को होने वाले पब्लिक ऑडिट को भी बंद करवा दिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों में राशन कब तक पहुँच जाएगा, इसकी सूचना देने वाले

एसएमएस अलर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार को सौंपे गए चार्टर में यह भी माँग की गई कि बच्चों को रोज़ाना मध्याह्न भोजन या आँगनबाड़ियों में अण्डे, दूध और फल दिए जाएँ। चार्टर में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली के सभी जिलों में मातृत्व अधिकारों का क्रियान्वयन बाकी है। इसमें कहा गया, "एनएफएसए के अनुच्छेद 4 के तहत गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को मातृत्व अधिकार के तहत 6 हजार रुपए मिलने चाहिए।"

(The Hindu, 24 March 2016)

बजट में अपनी माँग को शामिल करवाने के लिए जनता को कौन–कौन से उपाय करने होंगे?

19.4 कर

सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कर (Tax) होता है। सरकार कई तरह के कर से आय संग्रहित करती है। आपने इनमें से कुछ करों जैसे मूल्य सवंर्द्धित कर (VAT), सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि के बारे में सुना होगा। इन करों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है– पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर।

19.4.1.1 अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। आपने किसी वस्तु के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ यह लिखा जरूर पढ़ा होगा– कर सहित। इसका सीधा–सा अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं जैसे टेलीफोन या मोबाइल के बिलों में कर शामिल रहता है। आइए, हम कुछ महत्वपूर्ण करों को उदाहरणों के साथ समझते हैं।

19.4.2 उत्पाद शुल्क

यह कारखानों में उत्पादित या निर्मित होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। निर्मित वस्तुओं के कारखाने के गेट से बाहर होने से पहले उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। कारखाने का मालिक या प्रबंधक उत्पादन की मात्रा के अनुसार सरकार को यह शुल्क देता है।

उत्पाद शुल्क वैसे तो कारखानों से वसूल किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है। कारखाने का मालिक अपने सामान को बेचते समय उसकी कीमत में कर भी जोड़ देता है। उदाहरण के लिए एक टीवी सेट की कीमत 10 हजार रुपए है। कम्पनी इस पर 1200 रुपए का उत्पाद शुल्क देती है। तो इस शुल्क को भी टीवी की कीमत में जोड़ देती है। उपभोक्ता जब टीवी खरीदता तो उसे यह शुल्क भी चुकाना पड़ता है।

वस्तुओं पर करारोपण करने से उनकी कीमतें तो बढ़ती ही हैं, लेकिन कुछ कच्चे माल पर भी कर लगाने से उनके दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल बनाने के लिए स्टील पाइप्स ज़रूरी है। स्टील कम्पनियों को लौह अयस्क और कोयले की ज़रूरत होती है। सरकार अगर लौह अयस्क पर कर बढ़ाती है तो इसका प्रभाव साइकिल उद्योग पर भी पड़ेगा। स्टील से बनने वाली सभी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह केवल लौह अयस्क पर ही कर लगाने से अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया एक–दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी रहती है। जिसके कारण इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है।

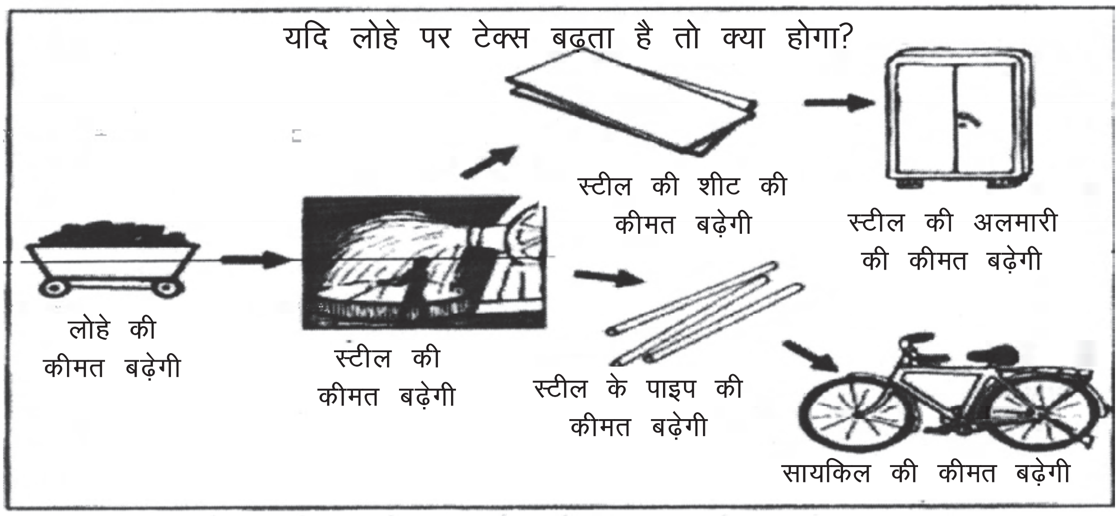

चित्र 19.4 : करों में वृद्धि का प्रभाव

पेट्रोल और डीजल का उपयोग वाहनों, मोटर पम्प्स, जेनरेटिंग सेट्स आदि में होता है। अगर पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ता है तो क्या होगा?

कोई भी वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद विक्रेताओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरती है। उत्पाद शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है जबकि बिक्री कर (Sales Tax) वस्तु के विक्रय पर लिया जाता है। आप अगली बार जब कोई वस्तु खरीदें तो उसका पूरा बिल लीजिए। उस बिल में वस्तु की कीमत के साथ मूल्य सवंर्द्धित कर (VAT) भी जुड़ा हुआ दिखाई देगा। आपके बिल में लिखा बिक्री कर सूचित करता है कि इस कर को वस्तु बेचने वाला सरकार को देता है। उत्पाद शुल्क की तरह ही बिक्री कर का भार भी उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है। जिससे उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।

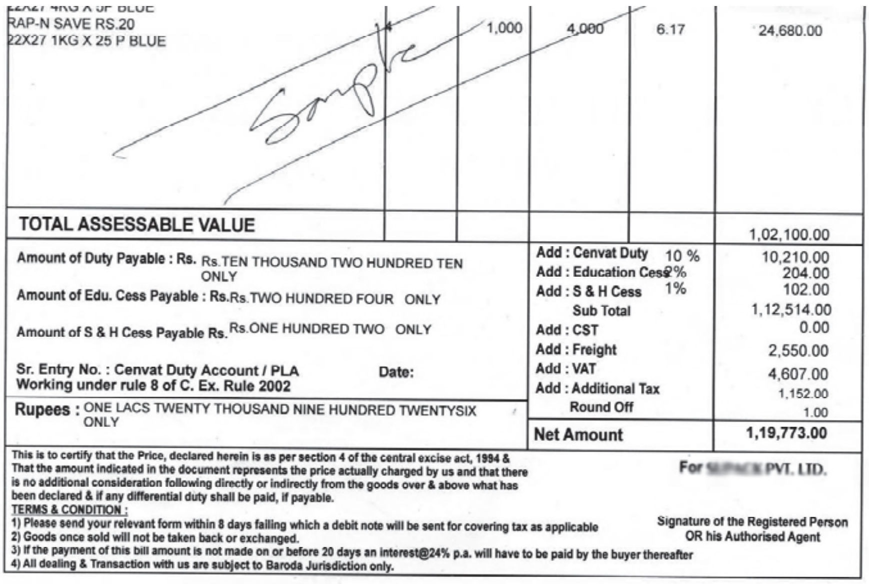
RAP-N SAVE RS.20
22X27 1KG X 25 P BLUE

		1,000	4,000	6.17	24,680.00
TOTAL ASSESSABLE VALUE					1,02,100.00

Amount of Duty Payable : Rs. Rs.TEN THOUSAND TWO HUNDRED TEN ONLY
Amount of Edu. Cess Payable : Rs.Rs.TWO HUNDRED FOUR ONLY
Amount of S & H Cess Payable Rs. Rs.ONE HUNDRED TWO ONLY
Sr. Entry No. : Cenvat Duty Account / PLA Date:
Working under rule 8 of C. Ex. Rule 2002
Rupees : ONE LACS TWENTY THOUSAND NINE HUNDRED TWENTYSIX ONLY

Add : Cenvat Duty 10 %	10,210.00
Add : Education Cess 2%	204.00
Add : S & H Cess 1%	102.00
Sub Total	1,12,514.00
Add : CST	0.00
Add : Freight	2,550.00
Add : VAT	4,607.00
Add : Additional Tax	1,152.00
Round Off	1.00
Net Amount	1,19,773.00

This is to certify that the Price, declared herein is as per section 4 of the central excise act, 1994 & That the amount indicated in the document represents the price actually charged by us and that there is no additional consideration following directly or indirectly from the goods over & above what has been declared & if any differential duty shall be paid, if payable.

For [illegible] PVT. LTD.

TERMS & CONDITION :
1) Please send your relevant form within 8 days failing which a debit note will be sent for covering tax as applicable
2) Goods once sold will not be taken back or exchanged.
3) If the payment of this bill amount is not made on or before 20 days an interest@24% p.a. will have to be paid by the buyer thereafter
4) All dealing & Transaction with us are subject to Baroda Jurisdiction only.

Signature of the Registered Person OR his Authorised Agent

चित्र 19.5 : बिल का एक नमूना

आइए हम उसी टीवी का उदाहरण लेते हैं, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इससे हम जान सकेंगे कि कर के कारण किसी वस्तु की कीमतों में कितनी अधिक वृद्धि हो जाती हैं।

लाभ और कर का अनुपात अलग–अलग वस्तुओं और राज्यों के हिसाब से अलग–अलग हो सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु चाहे कोई भी हो, उसकी कीमत में कर जुड़ा रहता है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं पर भी कर लगता है। सेवा कर (Services Tax) के कुछ सामान्य उदाहरण हैं- स्पीड पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल सेवा, रेस्टॉरेंट्स, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बों में सफर आदि।

यहाँ सभी आँकड़े रुपयों में दिए गए हैं।

निर्माण की लागत, निर्माता के मुनाफे सहित	10,000
उत्पाद शुल्क	1,200
परिवहन, संग्रहण और रिटेलिंग की लागत	1,000
विक्रेता का लाभ	1,000
बिक्री कर	1,650
उपभोक्ता के लिए कीमत	14,850

वस्तुओं पर लगने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कर सीमा शुल्क है जो विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विदेश से लौट रहा है और अपने साथ एक कैमरा खरीदकर ला रहा है तो उसे हमारे देश के हवाई अड्डे पर उस कैमरे पर सीमा शुल्क चुकाना होगा। अनेक कारखानों को विदेशों से मशीनें या कच्चा माल आयात करने पर भी उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता है।

टेलीविजन वाले उदाहरण में उपभोक्ता को टीवी की कीमत का कितना प्रतिशत कर के रूप में चुकाना पड़ा?
यदि दो व्यक्ति एक जैसा सामान बनाते हैं लेकिन इनमें से एक व्यक्ति कर देने से बच जाता है तो वह बाज़ार में किसका किस तरह से फायदा उठा सकता है?
अगर लौह अयस्क पर कर बढ़ जाता है तो किन–किन वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ उदाहरण दीजिए।

परियोजना कार्य :

ऐसे कुछ बिल एकत्र कीजिए जिनमें कर का उल्लेख हो और इन बिलों को चिपकाकर एक पोस्टर बनाइए।

19.4.1.2 मूल्य संवर्धित कर (Value Added Tax) के रूप में अप्रत्यक्ष कर

तारा ने अपने स्कूल के कम्प्यूटर के लिए साईं राम कम्प्यूटर से दो हार्ड ड्राइव खरीदी। बगैर वैट के बिल पर इसकी कुल कीमत 5000 रुपए थी। इस पर 5 प्रतिशत वैट लगाया गया। वैट के रूप में 250 रुपए की राशि जुड़ने के बाद उन हार्ड ड्राइव की कुल कीमत 5250 रुपए हो गई।

साजिदा ने अपने घर के लिए एक इन्वर्टर बैटरी खरीदी। दुकानदार ने जो बिल दिया, वह इस तरह था –

सामान	राशि (रु. में)
बैटरी	9,165
वैट 12.5% +	1,146
कुल	10,311

प्रीति ने एलपीजी सिलेण्डर खरीदा, लेकिन बिल में वैट जीरो प्रतिशत था। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वैट (VAT) नहीं लिया जाता।

पिछले करीब एक दशक से वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में बदल दिया गया है और इसे नाम दिया गया है वैट (VAT)। यह उत्पाद और बिक्री कर दोनों के लिए किया गया है। इसे समझने के लिए हम नीचे दिए गए उदाहरण को देखते हैं –

मान लीजिए एक बिस्किट निर्माता एक विश्वसनीय व्यक्ति से कच्चा माल खरीदता है। वह व्यक्ति उस बिस्किट निर्माता को इस तरह का बिल देता है –

सामग्री	सामग्री की लागत	कर	कुल बिल
कच्ची सामग्री जैसे गेहूँ, आटा, शक्कर आदि	रु. 90	रु. 10	रु. 100

अब मान लीजिए वह बिस्किट निर्माता 450 रुपए की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, ऑफिस और कारखाने का किराया आदि शामिल है। वह इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपया भी जोड़ लेता है तो अब कुल कीमत (आउटपुट) 500 रुपए हो गया। वह इस बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है। याद रखिए निर्माता को बिस्किट की बिक्री पर कर चुकाना होगा। मान लीजिए कर की यह दर 10 प्रतिशत हैं तो उसे कितना कर चुकाना होगा?

पुरानी व्यवस्था के तहत बिस्किट निर्माता को कर के रूप में 50 रुपए चुकाने होते (500 रुपए पर 10 प्रतिशत की दर से)। इस तरह सरकार को कुल मिलाकर 60 रुपए (10 + 50 रुपए) कर के रूप में मिलते। (इसमें से 10 रुपए का कर कच्ची सामग्री के विक्रेता के द्वारा चुकाया गया है।)

लेकिन मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली (वैट) में उत्पादक केवल मूल्य संवर्द्धन पर ही कर चुकाता है। कुल उत्पादित माल (आउटपुट) 500 रुपए का है। खरीदी गई कच्ची सामग्री (इनपुट) की लागत 100 रुपए है। इस तरह मूल्य संवर्द्धन, आउटपुट और इनपुट का अंतर है। इस मामले में यह 400 रुपए है। इस तरह उस बिस्किट निर्माता को 10 प्रतिशत के हिसाब से केवल 40 रुपए कर चुकाने होंगे। इस निर्माण में जिस इनपुट का इस्तेमाल किया गया है, उस पर पहले से ही कर दिया जा चुका है। इस पर दोबारा कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रणाली में सरकार को कुल मिलाकर 10+40 = 50 रुपए का कर मिलेगा।

इस तरह स्पष्ट है कि मूल्य संवर्द्धन कर प्रणाली में निर्माता को कम कर चुकाना पड़ा, क्योंकि उसे इनपुट पर कर चुकाने की जरूरत नहीं है। वैट का एक और लाभ है। सभी निर्माताओं और व्यापारियों को बिक्री और खरीदी का सही रिकॉर्ड रखना होगा। इसी बिल के आधार पर वे दावा कर सकेंगे कि इनपुट पर पहले ही कर का भुगतान हो चुका है। इससे कर विभाग (कर अधिकारी) भी विक्रेता और क्रेता के बिलों का मिलान कर सकेंगे। इस तरह इस प्रणाली में कर चोरी की संभावना काफी कम होगी।

19.4.1.3 आगे की ओर........ वस्तु एवं सेवा कर (GST)

वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर आदि। इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर अलग–अलग कर हैं। इसके अलावा राज्यों में कर की दरें भी अलग–अलग हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है क्योंकि दोनों राज्यों में पेट्रोल पर बिक्री कर की दरों में अन्तर है। ऐसे ही और कई उदाहरण हैं। इसी कारण से राज्यों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा

होती है और उद्योग व्यापार भी एक राज्य से दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। हाल के वर्षों में नीति–निर्धारक लोग विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and services Tax) में बदलने पर विचार करते आ रहे हैं। यह कर भी मूल्य संवर्द्धन कर ही होगा और किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगेगा जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कर की दरें भी सभी राज्यों में एक समान रहेंगी।

– मूल्य संवर्द्धन कर के बारे में आपके क्या विचार हैं? चर्चा कीजिए।

रिक्त स्थान की पूर्ति करें –

तारा, साजिदा और प्रीति द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर................ (एक समान/अलग) दर से कर लगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ?

19.4.2प्रत्यक्ष कर

अभी हमने अप्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं लेकिन इसका भुगतान परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं को ही करना पड़ता है।

चित्र 19.6 : आयकर विभाग

लेकिन कुछ कर ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। ये कर व्यक्ति की आय या कंपनियों अथवा व्यापार से होने वाली आय पर लगता है। इन करों को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

हमारे यहाँ दो प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं – आयकर और निगम कर।

कारखाने या व्यापार करने वाली कंपनियों को निगम कर (Corporate Tax) चुकाना होता है। यह कर इन कंपनियों को अपने सभी खर्चों (कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतन) को काटने के बाद अर्जित आय पर देना होता है।

आयकर (Income Tax) व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर आयकर देना होता है।

आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आय कर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिनकी आय जितनी अधिक होती है उन्हें उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना होता है।

आय पर कर लेने की उचित विधि क्या है?

क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आयकर लेना उचित होगा? आइए हम इन तीनों व्यक्तियों पर विचार करते हैं –

व्यक्ति	कार्य	मासिक आय हर महीने (रुपए में)	निश्चित इनकम टैक्स (रु. में)
ज्योति	दैनिक मजदूर	1500	50
आसिफ	स्कूल शिक्षक	8000	50
जतिंदर	व्यापारी	30,000	50

ऊपर उल्लेखित तीनों व्यक्तियों से यदि एक समान आयकर लिया जाए तो क्या यह उचित होगा? ज्योति अगर अपने बच्चों को ठीक से दो वक्त का खाना भी नहीं खिला पाती है तो क्या उससे 50 रुपए का कर लेना ठीक रहेगा?

अब आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति की आय का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में ले लिया जाए। लेकिन क्या यह भी उचित होगा? मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का 10 प्रतिशत हिस्सा आयकर के रूप में देता है। गणना कीजिए कि नीचे उल्लेखित तीनों व्यक्ति कितनी राशि कर के रूप में भुगतान करेंगे।

व्यक्ति	मासिक आय (रुपए में)	आय कर (रुपए में)
ज्योति	1500	——
आसिफ	8000	——
जतिंदर	30,000	——

उपर्युक्त तालिका को देखकर हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों से एक ही दर से कर लेना उचित नहीं है क्योंकि अभी भी ज्योति के पास अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचेंगे। हो सकता है कि आसिफ के पास भी अपने घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हों। लेकिन जतिंदर से 20 प्रतिशत आय कर ले लिया जाए तब भी उसके पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि बच जाएगी।

आयकर को और अधिक न्यायोचित बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक निश्चित राशि से ज्यादा कमाने वालों से ही आयकर लिया जाना चाहिए। इस मामले में मान लो हम 7000 रुपए मासिक कमाई की न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि अधिक आय प्राप्त करने वालों को आयकर भी अधिक दर से भुगतान करना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं –

यदि आप इतना आय प्राप्त करते हैं	तो आप इस दर से कर देंगे
7000 रुपए से कम	0%
7001 से 15000 रुपए	10%
15,001 से 25,000 रुपए	20%
25,000 रुपए से ज्यादा	30%

गणना कीजिए कि अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना आयकर चुकाना होगा –

व्यक्ति	मासिक कमाई	कर (रुपए में)
ज्योति	1000	
आसिफ	6000	
जतिंदर	20,000	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार क्या अब कर दरें न्यायोचित है? इसकी चर्चा अपने शिक्षक के साथ करें।

हम सरकार द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कुछ करों के बारे में पढ़ चुके हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस टेबल को पूरा कीजिए।

आयकर 12%, निगम कर 21%, सीमा शुल्क 9%, उत्पाद शुल्क 14%, सेवा कर 10%, बिक्री कर 25% अन्य अप्रत्यक्ष कर 9%।

सरकार द्वारा संग्रहित कर

कर	कुल करों का प्रतिशत
प्रत्यक्ष कर	
1. निगम कर	21%
2.	
योग –	
अप्रत्यक्ष कर	
1	
2	
3	
4	
5	
योग –	
कुल कर	100%

सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है?

कांति की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए है और उसे इस पर 3000 रुपए आयकर के रूप

में देना पड़ता है। कमलेश की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए है और उसे आयकर के रूप में 5500 रुपए देना पड़ता है। अब बताइए कि ––

– इन दोनों में से कौन अधिक आयकर का भुगतान करता है?
– किसे कर के रूप में अपनी आय का ज्यादा हिस्सा देना होगा?
– इस स्थिति में जिस व्यक्ति की आय अधिक है, वह ....(कम / ज्यादा / बराबर) आयकर देगा।

19.5 करारोपण में न्यायसंगतता

हमें किस कर प्रणाली को अपनाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है? कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों–करोड़ों की संपत्ति है, जबकि एक बड़ा वर्ग दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाता है। इस प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है। इसलिए सरकार को सम्पन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए या न्यूनतम कर वसूलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित किए गए आय से गरीबों को बेहतर मौके उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। ज्योति, आसिफ और जतिंदर के उदाहरण की तरह ही कई देशों की सरकारें अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों से उच्च दर से कर वसूल करती हैं। आयकर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है, कुल कर में उनका हिस्सा भी सबसे अधिक रहेगा तथा जिनकी आय कम है, कुल कर में उनका हिस्सा सबसे कम रहेगा। जहाँ तक अप्रत्यक्ष कर की बात है, किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर देना होगा। अगर अमीरों और गरीबों के बीच कर के मामले में अंतर करना है तो इसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाए तथा विलासिता (लग्जरी) चीज़ों जैसे कार, लैपटॉप, एयर–कंडीशनर, रेस्टॉरेंट्स में भोजन करने पर टैक्स लगाया जाए।

वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और ज़रूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी कई वस्तुएँ और सेवाएँ हैं जिनका लोग सीधे उपभोग नहीं करते हैं जैसे डीजल, एल्युमिनियम, स्टील, मशीनें, ट्रक टायर्स आदि। लेकिन जब इन चीज़ों पर कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग से बननी वाली अन्य वस्तुओं या इनकी मदद से परिवहन होने वाली चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार, भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़ा खरीदते हों लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना होता है।

19.6 कर अपवंचना या कर चोरी

कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते बल्कि जितना कमाते हैं, उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। छुपाकर रखी हुई इस आय को काला धन कहा जाता है। कई कारखानों के मालिक, अमीर जमींदार, व्यापारी जितना कमाते हैं, उससे बहुत कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है, उनकी आय की गणना आसानी से की जा सकती है। उनकी आय पर कर जहाँ से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहाँ से ही सीधे काट लिया जाता है। इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल होता है। इन लोगों की आय के और भी अन्य स्रोत हो सकते हैं। चूँकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता इसलिए इनमें कई लोग दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को कृषि से अर्जित आय बता देते हैं और आसानी से कर की चोरी कर लेते हैं।

इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं जो अपने पास काला धन एकत्रित करके

रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय–समय पर कर चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापे भी मारे जाते हैं। विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सकें।

दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के स्थल अपेक्षाकृत कम होते हैं जैसे उत्पाद शुल्क कारखानों से, सीमा शुल्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों व बंदरगाहों से और बिक्री कर व्यापारियों से वसूल किया जाता है। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है जैसे– कई व्यापारी समुचित बिल जारी नहीं करके अपने अधिकारिक बही–खातों में बिक्री को बहुत कम दिखाते हैं। वैट का मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाली इस कर चोरी को कम करना है।

19.7 कर और व्यय – अंतर्राष्ट्रीय तुलना

कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य कई देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ–साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम हैं। नीचे दी गई तालिका में भारत सरकार द्वारा संग्रहित की गई कर और खर्च की कुल राशि की तुलना अन्य देशों के साथ की गई है।

तालिका : कर संग्रहण और कुल खर्च (जीडीपी के प्रतिशत में)

देशों के नाम	कुल कर संग्रहण	कुल खर्च	मानव पूँजी पर खर्च
चीन	19.4	29.7	7.2
भारत	16.6	26.6	5.1
ब्राजील	35.6	40.2	11
कोरिया	24.3	20	8.4
वियतनाम	22.2	28	8.8
द. अफ्रीका	28.8	32	10.7
तुर्की	29.3	37.3	7.2
रूस	23	38.7	7.2
ब्रिटेन	32.9	41.4	13.4
अमेरिका	25.4	35.7	13.3

(स्रोत – आर्थिक सर्वे, 2015–16)

इस तालिका से पता चलता है कि भारत में कर संग्रहण (जीडीपी प्रतिशत में) अन्य देशों की तुलना में कम है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है जिसके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता काफी कम है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है।

कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है। जब कर का संग्रहण कम होता है तब राजस्व में भी कमी आती है। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम हो जाती है। ऊपर दी गई टेबल का कॉलम 3 कुल खर्च और कॉलम 4 मानव पूँजी पर होने वाले खर्च को दर्शाता है। मानव पूँजी पर होने वाले खर्च में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल

रहता है। हम पूर्व पृष्ठ की तालिका को देखकर कह सकते हैं कि मानव पूँजी पर होने वाला खर्च भी सीधे–सीधे कुल कर संग्रहण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूँजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव मानव विकास के प्रदर्शन पर पड़ता है।

सारांश

सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर ज़रूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने, लोगों को उनकी आजीविका दिलवाने, देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि कार्य करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के लिए राजस्व की व्यवस्था का लेखा–जोखा होता है। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और इस तरह लगभग हर व्यक्ति परोक्ष रूप से सरकार को कर देता है। प्रत्यक्ष कर निजी तौर पर दिया जाता है। व्यक्ति अपनी आय पर और कंपनियाँ अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देती हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायसंगत होते हैं लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रहण में इसका हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों से होने वाले कर संग्रहण को करों की चोरी प्रभावित करता है। अगर कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके तो सरकार आम लोगों के हित में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है।

अभ्यास

YEFYYU

1. सही विकल्प का चयन कीजिए

   1. मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है–

      (क) 50 दिन (ख) 100 दिन

      (ग) 150 दिन (घ) 200 दिन

   2. सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है –

      (क) ऋण (ख) सरकारी कंपनी का लाभ

      (ग) कर (घ) इनमें से कोई नहीं

   3. सरकार की आय और व्यय का लेखा–जोखा होता है –

      (क) राजस्व (ख) कर

      (ग) लाभ (घ) बजट

   4. केन्द्रीय बजट पारित किया जाता है –

      (क) संसद में (ख) विधानसभा में

      (ग) राज्य सभा में (घ) इनमें से कोई नहीं

   5. प्रत्यक्ष कर है –

      (क) मनोरंजन कर (ख) सेवा कर

      (ग) बिक्री कर (घ) इनमें से कोई नहीं

6. सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं हैं –
   (क) कार (ख) बिजली
   (ग) सड़क (घ) रेल

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
   1. देश के लोगों को .... सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।
   2. FSSAI का पूरा नाम है – ....
   3. .... में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है।
   4. कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाना वाला शुल्क .... शुल्क कहलाता है।
   5. सिनेमाघर में चलचित्र देखने पर लगने वाला कर .... कर है।
   6. .... कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है।
   7. अप्रत्यक्ष कर .... और .... पर लगाया जाता है।
3. सरकार के लिए बजट क्यों ज़रूरी है? बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है?
4. आयकर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है?
5. उचित संबंध जोड़िए –

उत्पाद शुल्क	निजी आय पर कर
बिक्री कर	कंपनियों और व्यापारियों द्वारा अर्जित वार्षिक मुनाफे पर कर
सीमा शुल्क	वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर कर
आयकर	वस्तुओं की बिक्री पर कर
निगम कर (कारपोरेट टैक्स)	विदेश से लाई गई चीजों पर कर

6. इस्पात, माचिस, घड़ियाँ, कपड़े, लौह अयस्क आदि पर करों में वृद्धि का प्रभाव अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर होता है क्यों? इनमें से किन चीज़ों पर कर की वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर सबसे अधिक पड़ेगा और क्यों?
7. सामान्य वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, तेल आदि का उपभोग प्रायः सभी करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन पर लगाया जाने वाला कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है?
8. चार दोस्त मिलकर एक साथ एक मकान किराए पर लेते हैं। इसका मासिक किराया 2000 रुपए है। इन चारों में इसका बंटवारा कैसे होगा?

   इनमें से दो लोगों की मासिक आय 3000 रुपए है, जबकि दो अन्य लोगों की मासिक आय 7000 रुपए। क्या किराए में बंटवारे का कोई और अन्य उपाय है ताकि सभी लोगों को इसका भार एक जैसा महसूस हो?

   किराए में बंटवारे का आप कौन–सा तरीका पसंद करेंगे और क्यों?
9. आय पर कर और वस्तुओं पर कर – इन दोनों में से कौन–सा कर अमीरों को और कौन–सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? कारण बताइए।
10. वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है
11. आयात कर और निर्यात कर में अन्तर लिखिए।